

प्रेषक

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

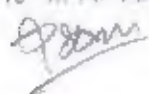
विषय-

देहरादून दिनांक: 29 अप्रैल, 2009
वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को विद्युतीकरण कार्य (अनुसूचित जाति उपयोजना) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 524/जि०को०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनांक 24.03.2008 एवं वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25.03.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० को जिला योजनान्तर्गत (अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ) अनुमोदित कार्य हेतु ऋण के रूप में रु० 1,43,00,000.00 (रु० एक करोड़ तेत्तास लाख मात्र) की धनराशि संलग्नक-1 में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार आपके निर्वर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार कर एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा तथा आहरण तिथि के तीन दिन के अन्दर धनराशि का हस्तान्तरण अपने सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों को किया जायेगा, जिसकी सूचना सम्बन्धित आयुक्त, जिलाधिकारी तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को भी दी जायेगी।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपदों में वे ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे जो चालू योजना के हों एवं जनपद की जिला सेक्टर की योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा चयनित एवं अनुमोदित हैं।
- 3- कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्य का विस्तृत आगमन, कार्य का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, सामान्यित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर वास्तविक विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्य का क्रियान्वयन परियोजना मॉड में यथोचित बारचार्ट/पर्ट चार्ट आदि पूर्ण में निश्चित कर किया जायेगा।
- 4- उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, संबंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्य एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।
- 6- व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैंडबुक स्टोर प्रवर्ज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली तथा टेंडर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
- 7- नये कार्य पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगमन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर पर अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 8- स्वीकृत कार्य की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9- आवश्यक सानग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 10- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रु० 6.5% की दर निर्धारित है। इस ऋण पर भी व्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा वित्त वर्ष की दशा में 1.0% अतिरिक्त बिलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 वार्षिक किश्तों में (व्याज सहित) माह अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ होगा।



- 11- प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कौषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेगे।
 - 12- उत्तराखण्ड फावर कारपोरेशन लि० जब भी किश्तों का भुगतान करे ब्याज भी अवश्य जमा करे एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर भेजे:-
1- कौषागार का नाम, 2- चालान सं०, 3- जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4- शासनादेश संख्या और एस०एल०आर० का संदर्भ, 5- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।
 - 13- ऋण प्रदानकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से अवश्य करे तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा ले।
 - 14- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब वह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।
 - 15- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2010 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रूप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा।
 - 16- जिला योजना में सामान्य जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ धनराशि अलग से निर्गत है।
 - 17- अवमुक्त की जा रही धनराशि का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।
 - 18- स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लेखानुदान के अनुदान सं० 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 0601-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारिषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-91-जिला योजना-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं० 205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25.03.2009 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

सलन्क- यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या: 1011 /1(2)/2009-06(1)/104/08, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सलन्क की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
 - 2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
 - 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 - 5- समस्त जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, उत्तराखण्ड।
 - 6- कौषाधिकारी, देहरादून।
 - 7- वित्त अनुभाग-2/बजट निदेशालय।
 - 8- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 9- प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
 - 10- विशेष सैल, ऊर्जा।
 - 11- गार्ड फाईल हेतु।
- सलन्क- यथोक्त।

आज्ञा से,

(एम०एम० सेमवाल)

अनु सचिव

जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विवरण ।

(धनराशि लाख रु०में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि
1	नैनीताल	10.00
2	ऊधमसिंह नगर	00
3	अल्मोड़ा	12.67
4	पिथौरागढ़	9.49
5	बागेश्वर	1.33
6	चम्पावत	7.27
7	देहरादून	15.60
8	पौड़ी	18.99
9	टिहरी	21.95
10	चमोली	10.87
11	उत्तरकाशी	5.40
12	रूद्रप्रयाग	17.43
13	हरिद्वार	12.00
	योग :-	143.00

(रुपये एक करोड़ तैंतालिस लाख मात्र)

२९.५.०९
(सौरभ जैन)
अपर सचिव